

## पेटेंट कानून की हकीकत



पेटेंट वो कानून होता है जो किसी वस्तु विशेष के प्रति आविष्कारक या उत्पादक को सर्वाधिकार उपलब्ध करवाता है। भारत में 1911 से 1970 तक अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया पेटेंट कानून लागू था। 1970 के बाद उसमें संशोधन हुए जिससे भारतीय उद्योग खासकर दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ उतनी सुरक्षित नहीं रह गई हैं जितनी 1970 के पेटेंट कानून के समय थीं। प्रस्तुत लेख भाई राजीव दीक्षित जी के एक भाषण का लिखित स्वरूप है जिसमें मुख्य बिंदुओं की संक्षेप में चर्चा की गई है। आप इस व्याख्यान को श्रद्धेय भाई राजीव जी के श्रीमुख से नीचे दिए गए लिंक पर भी सुन सकते हैं।

ऑडियो लिंक: [https://docs.google.com/file/d/0B8n\\_36gK-KF4NE5zZ3k0ODVkJLUU/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/file/d/0B8n_36gK-KF4NE5zZ3k0ODVkJLUU/edit?usp=sharing)

विदेशी बाज़ार को भारत में सुरक्षा देने के लिए अंग्रेज़ों ने एक पेटेंट कानून बनाया, सन 1911 में। इस कानून में उत्पाद केन्द्र में था जिसका मतलब था कि पेटेंट उत्पाद की सुरक्षा करेगा, उत्पाद को बनाने वाली तकनीक की नहीं। अगर कोई कंपनी अमुक दवाई बनाकर उस पर पेटेंट हासिल कर लेती है तो कोई और कंपनी वही दवाई किसी भी अन्य तरीके से नहीं बना सकती। इससे होता यह था कि इस पेटेंटेड दवाई की कंपनी बाज़ार में मनमाना दाम रखकर खूब पैसा कमाती थी। यही कारण था कि भारत में 1911 से लेकर 1970 तक दवाई बनाने की केवल मुट्ठीभर कंपनियाँ थीं और भारत को दवाइयों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। देश के लाखों करोड़ लोग इसीलिए मर जाते थे क्योंकि उन्हें समय पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती थीं। महत्वपूर्ण दवाइयाँ तो बिल्कुल ही नहीं बनती थीं भारत में। उस समय भारत केवल 65-70 करोड़ रुपए की दवाइयों का ही उत्पादन कर पाता था।

सन 1970 में, पेटेंट कानून वर्षों की बहस के बाद संशोधित किया गया। इस संशोधन में उत्पाद की जगह प्रक्रिया पर पेटेंट देने का प्रावधान रखा गया जिसका अर्थ है, अमुक दवाई बनाने के लिए प्रक्रिया पेटेंट कराई जा सकती है परंतु उत्पाद नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि एक ही दवाई को कई कंपनियाँ अलग अलग तरीके से बनाने लगीं और इस तरह बाज़ार में प्रतिस्पर्धा हो गई जिससे दवाइयों के दाम गिर गए। भारत को अब दवाइयाँ आयात नहीं करनी पड़ती थीं उल्टा सन 1997 तक भारत 2000 करोड़ की दवाइयाँ निर्यात करने लगा था! जहाँ 1970 से पहले तक भारत में केवल 65 करोड़ की ही

दवाइयाँ बनती थीं, वहीं अब भारत में 8000 करोड़ की दवाइयाँ बनने लगी थीं एकलौते इस संशोधन के बल पर! इसके अलावा भारत में दवाइयों का स्तर बहुत उत्कृष्ट हो चुका था जो जर्मनी और अमरीका की दवाइयों से कहीं भी पीछे नहीं था। दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दवाइयाँ अगर कहीं बन रही थीं तो केवल भारत में जिसके बाद दूसरा नंबर था बंगलादेश का। इस प्रतिस्पर्धा की सबसे अच्छी बात यह थी कि और देशों के मुकाबले दवाइयों के अनुसन्धान में हम पैसा तो कम खर्च कर रहे थे लेकिन गुणवत्ता उनके बराबर या उससे अधिक थी!

1970 के पेटेंट कानून में पेटेंट की अवधि 7 साल के लिए होती थी और इसमें किसी भी कंपनी को विदेश से आयात करने की अनुमति नहीं थी। एक कानून के तहत उनको दवाई का निर्माण यहीं करना होता था। इससे होता यह था कि आयात करने पर दवा की कीमत बढ़ जाती थी और विदेशी कंपनियों का मुनाफा आसमान छूने लगता था। 1999 से 2005 के मध्य पेटेंट कानून में हुए संशोधन के बाद अब स्थिति यह है:

1. पेटेंट की अवधि 7 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।
2. विदेश में दवाई बनाकर भारत में बेचने पर भी पेटेंट मिल सकता है।
3. पेटेंट अब उत्पाद पर भी दिया जाने लगा है और प्रक्रिया पर भी।
4. कोई भी कंपनी एक ही दवाई को कई नाम से बनाकर बेच सकती है।

उपरोक्त लिखित बिंदु इस संशोधन के वो मुख्य बिंदु हैं जिनकी वजह से कई गंभीर परिणाम हुए हैं। ये संशोधन एक संधि का परिणाम है जिस पर अन्य देशों की तरह भारत ने भी अमरीका और यूरोप के दबाव में आकर हस्ताक्षर किए। जब एक ही विदेशी कंपनी प्रक्रिया पर भी पेटेंट ले ले और उत्पाद पर भी तो समझ लीजिए कि कोई भी अन्य कंपनी न तो वो फॉर्मूला ले सकती है और

न ही वो दवाई बना सकती है। इससे उस दवाई की कीमत आसमान छूएगी और भारतीयों के पास मरने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा।

जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको दवाई लिखकर देता है। जब दवा का कोई असर नहीं होता तो आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाई का नाम बदल देता है। दवा फिर असर नहीं करती और डॉक्टर फिर दवाई का नाम बदल देता है। दवा फिर असर नहीं करती। हो यह रहा है कि डॉक्टर दवाई का नाम तो बदल रहा है पर दवाई है एक ही! यह एक ऐसा कुचक्र है जिसकी सुरक्षा यह पेटेंट कानून करता है और विदेशी कंपनियाँ लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में दवाइयाँ ब्रांड से बिकती हैं, अपने असली नाम से नहीं। इनका असली नाम दवाई का फोर्मुला ही होता है। उदाहरण के तौर पर Crocin एक ब्रांड है लेकिन उसका असली नाम Crocetin di-gentiobiose ester है। वहीं अमरीका में दवाईयों के ब्रांड कोने में पड़े होते हैं लेकिन उनका फोर्मुला स्पष्ट रूप से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। इसी तरह विश्व के कई देशों जैसे रूस, जापान, चीन में दवाईयों के नाम राष्ट्रीय भाषा में लिखा होता है ताकि एक साधारण आदमी भी समझ सके कि वह क्या खा रहा है। भारत में भी निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है किन्तु होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा करने से लाखों करोड़ का गबन नहीं हो सकेगा जो बिना प्रशासन की सहायता के संभव नहीं है!

भारत में 80000 से अधिक दवाईयों के ऐसे फोर्मुले हैं जो भारतीयों के लिए किसी काम के नहीं हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो हजारों ऐसी दवाइयाँ हैं जो फालतू हैं! AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) के एक अनुसन्धान के अनुसार भारत को केवल 250 दवाईयों की ही आवश्यकता है

परंतु भारत में हज़ारों दवाइयाँ धड़ल्ले से बिक रही हैं। मजे की बात यह है कि एक भी विदेशी कंपनी भारत में आवश्यक दवाई का निर्माण/आयात नहीं करती! उदाहरण के तौर पर:

- ब्रुफेन (Brufen) - विश्व के 17 देशों में प्रतिबंधित है क्योंकि इससे आँतों में घाव और अल्सर होता है। दर्द को कम करने के लिए केवल 10mg ब्रुफेन की आवश्यकता होती है लेकिन यह 250-400mg की टेबलेट में आती है।
- एस्पिरिन (Aspirin) - विश्व के 40 देशों में प्रतिबंधित है। यह केमिकल सीधा स्नायु तंत्र (nervous system) पर असर करता है।
- पेरासीटामोल (Paracetamol) - जापान समेत 12-15 देशों में प्रतिबंधित है। जापान में बच्चों को यह बहुत अधिक दी जाती थी। वहाँ के लगभग डेढ़ लाख बच्चे विकलांग हो गए। जापान सरकार ने एक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट WHO (World Health Organization) को सौंपी। रिपोर्ट में पता लगा कि पेरासीटामोल विकलांगता का कारण है। उस दिन के बाद से जापान में पेरासीटामोल प्रतिबंधित है परंतु भारत में धड़ल्ले से बिकना चालू है।

इस नए संशोधन के बाद Reversal of Burden of Proof का एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत अगर कोई पेटेंट का उल्लंघन करता है तो केवल उसे ही यह साबित करना पड़ेगा कि वह निर्दोष है। जो कंपनी आरोप लगायेगी, वह आरोप लगाने के बाद चुपचाप बैठ जाएगी। इससे होगा यह कि कल को कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी पर आरोप लगाती है तो विदेशी कंपनी तो चुपचाप अपना धंधा करती रहेगी परंतु आरोपित कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा जब तक कि वह खुद को निर्दोष नहीं साबित कर देती! सवाल

यह उठता है कि अगर देश पर कल को कोई विपत्ति आयेगी और देश को करोड़ों की तादाद में दवाईयों की जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं विदेशी कंपनियों से मनमाने दाम पर सरकार को दवाईयाँ खरीदनी पड़ेंगी जिससे देश की मुद्रा कम होगी और यदि स्थिति युद्ध की हुई तो अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़नी पूर्णतया संभव है! संसद में बैठे लोग इस बात से वाकिफ होते हैं और फिर भी यह विनाश का बीज बोने देते हैं। इसकी एवज में विदेशी कंपनियाँ करोड़ों की रिश्वत दे देती है। यही नहीं संसद में इन्हीं विदेशी कंपनियों के MP होते हैं जो तब खड़े हो जाते हैं जब कोई इन विदेशी कंपनियों की पोल खोलने की कोशिश करता है!

राजीव दीक्षित जी ने एक बार अपने कुछ सांसद मित्रों से अनुरोध कर संसद में बहस करवाई कि बेबी पाउडर पर रोक लगे। यूरोप में बेबी पाउडर प्रतिबंधित है क्योंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जब यह बहस चल ही रही थी तो सांसदों की पूरी एक लॉबी खड़ी हो गई जिसने हंगामा करके इस रोक प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया! सरकार ने इतना कर दिया कि बेबी पाउडर के डब्बों पर छोटे अक्षरों में लिखवा दिया कि “माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है”। जगह जगह सेमिनार करवाए गए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है और इसके लिए करोड़ों रूपए भी खर्च किए गए। सबसे पहली बात तो यह कि भारत के पैसे वाले लोग ही इन डब्बों का प्रयोग करते हैं, गरीब तो इन्हें खरीद भी नहीं सकता। ये लोग ऐसे सेमिनार में जाना तो दूर, घर में टीवी पर यह देखते हैं कि बच्चे को नेस्ले पिलायें या नेस्टम! फिर सरकार इतने पैसे खर्च करके क्या सिद्ध करती है? इस दोगलेपन से तो कहीं अच्छा होता कि इन डिब्बों को ही बंद करवा दिया जाता। देश के कितने रूपए बाहर जाने से बचते! हम इनसे पूछते हैं

कि रानी लक्ष्मी बाई, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, गुरु गोबिंद सिंह जी आदि महावीरों ने कौन सा बेबी पाउडर पीया था?

क्या आपको पता है, बूस्ट और होर्लिक्स जैसे हेल्थ टोनिक कैसे बनते हैं?

मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो शेष रह जाता है, वह फालतू चीज़ ही आपका हेल्थ टोनिक है! गाँव में यह जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है जो 20-25 रुपए किलो के भाव से मिलता है। 100 बूस्ट के डब्बे खा कर जितनी शक्ति आपको नहीं मिलेगी उससे कहीं अधिक शक्ति आपको एक किलो मूंगफली गुड़ के साथ खाने से मिल जाएगी! किन्तु सरकार को अगर भारत के स्वास्थ्य की चिंता होती, तब ही इन चीज़ों का प्रचार होता।

अमरीका के एक डॉक्टर ने हल्दी के औषधीय गुणों पर और एक अन्य अमरीकन डॉक्टर ने नीम के औषधीय गुणों को ही पेटेंट करवा लिया। उनका कहना है कि उन्होंने नीम और हल्दी को खोज निकाला है। वे मूर्ख इतना भी नहीं जानते कि भारत जैसे देश में पता नहीं कितने वर्षों से इन औषधीयों का उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का भी पेटेंट भारत को कर लेना चाहिए क्योंकि इन विदेशियों का कोई भरोसा नहीं, कल कहें कि संस्कृत उन्हीं के यहाँ की भाषा थी इसीलिए उसे भी पेटेंट करवा लिया! इसी तरह भारत की सुरक्षा कई मामलों में खतरे में है। भारत की खुफ़िया एजेंसी RAW की एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें यह खबर थी कि विदेशी कंपनियाँ अपने साथ CIA (अमरीकन एजेंट) ला रही हैं।

भारत में दवाईयों के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का एक विभाग था जिसको DPCO (Drugs Price Control Order) कहते थे। इस विभाग का काम था कि दवाईयों की बिक्री और उसकी कीमत को वश में रखना। जब से भारतीय पेटेंट कानून में नए संशोधन हुए हैं, तब से यह विभाग बंद पड़ा है। इसको बंद करने वाले थे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने अपने खेमे के मंत्रियों और गठबंधन की भलाई के लिए कई काम किए जिनका भुगतान आज देश कर रहा है। इनकी उत्कृष्ट नीतियों का ही परिणाम है कि आज देश के रुपये की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कोई औकात नहीं है, देश के किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, प्राकृतिक आपदाओं से निबटने के लिए हमें सेना पर निर्भर रहना पड़ता है और सीमाओं पर पकड़ ढीली करनी पड़ती है, देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपये से कम में जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं, चीन-पाकिस्तान-बंगलादेश हमें हलके में लेते हैं, 6000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियाँ भारत का दिन रात खून चूस रही हैं, हज़ारों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं और कोई कार्यवाही नहीं होती। आने वाले वर्षों में भारतीय किसानों और व्यापारियों को विदेशियों के हाथ बेचने का पूरा मास्टर प्लान तैयार है। आप चाहे किसी को वोट दें या न दें परंतु इस पार्टी को अब संसद में भेज कर ऐसी कोई भी लॉबी खड़ी होने से हमें रोकना है जो राष्ट्रविरोधी काम करते हों!

आप से फिर भेंट होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहें और भाई राजीव जी के इन राष्ट्रीय विचारों को बातचीत के जरिए प्रचारित-प्रसारित करते रहें!

वंदे मातरम् ...



